www.researchvidyapith.com ISSN (Online): 3048-7331

Research Vidyapith International Multidisciplinary Journal

(International Open Access, Peer-reviewed & Refereed Journal)

(Multidisciplinary, Monthly, Multilanguage)

*** Vol-2* *Issue-3* *March 2025***

आधुनिक भारत में डिजिटल अर्थव्यवस्था का विकास और उसका प्रभाव

डॉ0 संजीव रतन गुप्ता

एसोसिएट प्रोफ़ेसर, अर्थशास्त्र विभाग, संत तुलसी दास पीजी कॉलेज, कादीपुर, सुलतानपुर, यू.पी

सारांश

आधुनिक भारत में डिजिटल अर्थव्यवस्था ने आर्थिक संरचना और विकास प्रक्रिया में क्रांतिकारी परिवर्तन लाए हैं। डिजिटल इंडिया मिशन (2015) के तहत सरकार ने डिजिटल लेन–देन, ई–कॉमर्स, डिजिटल बैंकिंग, और इंटरनेट कनेक्टिविटी को बढ़ावा दिया, जिससे आर्थिक गतिविधियाँ तेजी से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्थानांतरित हुईं। आज डिजिटल भुगतान प्रणाली, जैसे यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, मोबाइल वॉलेट्स, और इंटरनेट बैंकिंग, भारतीय अर्थव्यवस्था का अभिन्न हिस्सा बन चुके हैं। डिजिटल अर्थव्यवस्था के बढ़ते प्रभाव से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) को वैश्विक बाजारों से जोड़ने में सहायता मिली है, जिससे छोटे व्यापारियों को नए अवसर प्राप्त हुए हैं। ई–कॉमर्स प्लेटफॉर्म (जैसे Amazon, Flipkart, और Myntra) ने उपभोक्ता व्यवहार में बदलाव लाया और ऑनलाइन खरीदारी को लोकप्रिय बनाया। साथ ही, डिजिटल हेल्थकेयर, ऑनलाइन शिक्षा, और रिमोट वर्किंग के विस्तार ने डिजिटल इनोवेशन को प्रोत्साहित किया। हालाँकि, डिजिटल अर्थव्यवस्था के समक्ष कई चुनौतियाँ भी हैं। साइबर सुरक्षा, डेटा गोपनीयता, डिजिटल विभाजन, और डिजिटल साक्षरता की कमी जैसी समस्याएँ अभी भी मौजूद हैं, जो डिजिटल विकास में बाधा उत्पन्न कर सकती हैं। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट एक्सेस और डिजिटल जागरूकता का अभाव डिजिटल असमानता को जन्म देता है। भविष्य में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ब्लॉकचेन, और 5जी तकनीक डिजिटल अर्थव्यवस्था को और अधिक सशक्त बनाएंगे। डिजिटल अवसंरचना को मजबूत करने, साइबर सुरक्षा उपायों को बढ़ाने और डिजिटल शिक्षा को प्राथमिकता देने से भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था को नई ऊँचाइयाँ मिल सकती हैं। कुल मिलाकर, डिजिटल अर्थव्यवस्था भारत के आर्थिक विकास, रोजगार सृजन, और नवाचार को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, जिससे देश आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है।

मुख्य–शब्द– डिजिटल अर्थव्यवस्था, डिजिटल इंडिया, ऑनलाइन भुगतान, ई–कॉमर्स, वित्तीय समावेशन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, साइबर सुरक्षा, डिजिटल विभाजन, आर्थिक विकास, नवाचार।

परिचय

डिजिटल अर्थव्यवस्था आधुनिक युग की एक महत्वपूर्ण अवधारणा है, जिसने आर्थिक गतिविधियों के संचालन, व्यापार प्रणाली और वित्तीय लेन–देन के तरीकों को नया स्वरूप प्रदान किया है। वैश्वीकरण और तकनीकी नवाचारों के चलते डिजिटल अर्थव्यवस्था न केवल विकसित देशों में, बल्कि भारत जैसे विकासशील देशों में भी आर्थिक विकास के एक प्रमुख स्तंभ के रूप में उभर रही है। डिजिटल अर्थव्यवस्था का विकास भारत की आर्थिक नीतियों, औद्योगिक प्रगति और सरकारी पहलों से गहराई से जुड़ा हुआ है। भारत सरकार द्वारा 'डिजिटल इंडिया' पहल की शुरुआत के बाद से डिजिटल अर्थव्यवस्था का प्रभाव व्यापक रूप से देखने को मिला है। इस पहल का उद्देश्य भारत को एक डिजिटली सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में परिवर्तित करना था। डिजिटल

अर्थव्यवस्था का प्रभाव वाणिज्य, बैंकिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, और सेवा क्षेत्रों में व्यापक रूप से देखा जा सकता है। इसके साथ ही, डिजिटल भुगतान प्रणाली और ई–कॉमर्स का विकास भारतीय उपभोक्ताओं के व्यवहार में एक महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आया है।

डिजिटल अर्थव्यवस्था एक ऐसी आर्थिक संरचना है, जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी का व्यापक उपयोग किया जाता है। इसमें सभी आर्थिक गतिविधियाँ डिजिटल प्लेटफार्मों पर संचालित होती हैं, जैसे कि ऑनलाइन व्यापार, ई–बैंकिंग, डिजिटल भुगतान, और ई–गवर्नेंस। भारत में डिजिटल अर्थव्यवस्था के विकास की जड़ें 1990 के आर्थिक सुधारों और सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति से जुड़ी हुई हैं। लेकिन इस क्षेत्र में वास्तविक परिवर्तन 21वीं सदी में हुआ, जब इंटरनेट की पहुँच और डिजिटल सेवाओं का विस्तार तेज़ी से हुआ।[1]

1991 में भारत ने आर्थिक उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण (स्च्ळ) नीतियों को अपनाया, जिससे आईटी और टेलीकॉम सेक्टर में निवेश को प्रोत्साहन मिला। इस अवधि में कई बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने भारत में अपनी सेवाएँ शुरू कीं, जिससे सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का विस्तार हुआ। 2000 के दशक में इनफोसिस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और विप्रो जैसी आईटी कंपनियों के उदय के साथ भारत ने वैश्विक डिजिटल बाजार में अपनी पहचान बनाई। 2008 में मोबाइल क्रांति के कारण भारत में इंटरनेट की पहुँच बढ़ी, जिससे डिजिटल सेवाओं की माँग में वृद्धि हुई। 2014 में 'डिजिटल इंडिया' अभियान की शुरुआत हुई, जिसमें सरकार ने ई–गवर्नेंस, डिजिटल वित्तीय सेवाओं और ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा दिया। 2016 में नोटबंदी के बादऐप और डिजिटल वॉलेट जैसी सेवाएँ अत्यधिक लोकप्रिय हुईं। 2020 महामारी के दौरान डिजिटल भुगतान, ऑनलाइन शिक्षा और वर्चुअल मीटिंग्स का अभूतपूर्व विस्तार हुआ। सरकार ने 'आत्मनिर्भर भारत' पहल के तहत स्टार्टअप और डिजिटल व्यवसायों को समर्थन देना शुरू किया।[2]

डिजिटल अर्थव्यवस्था के बढ़ते प्रभाव का सबसे बड़ा उदाहरण ई–कॉमर्स और ऑनलाइन व्यापार का तेज़ी से विस्तार है। भारत में फ्लिपकार्ट, अमेज़न, मिंत्रा, स्नैपडील जैसी कंपनियों ने ऑनलाइन खरीदारी को मुख्यधारा में ला दिया है। डिजिटल अर्थव्यवस्था भारत के आर्थिक विकास का प्रमुख कारक बन गई है। डिजिटल परिवर्तन, डिजिटल इंडिया पहल, डिजिटल भुगतान प्रणाली, ई–कॉमर्स और स्टार्टअप इकोसिस्टम ने भारतीय अर्थव्यवस्था को आधुनिक और प्रतिस्पर्धी बनाया है। हालाँकि, डिजिटल साक्षरता, साइबर सुरक्षा और डिजिटल विभाजन जैसी चुनौतियों का समाधान करना अभी भी आवश्यक है। आने वाले वर्षों में, 5 जी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और ब्लॉकचेन जैसी तकनीकों के माध्यम से भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था को और अधिक गति मिलने की संभावना है।

डिजिटल अर्थव्यवस्था के आर्थिक प्रभाव

डिजिटल अर्थव्यवस्था आधुनिक आर्थिक संरचना का एक महत्वपूर्ण घटक बन चुकी है। भारत में डिजिटल तकनीकों का व्यापक उपयोग, सरकार की डिजिटल इंडिया पहल और इंटरनेट की बढ़ती उपलब्धता ने देश के आर्थिक विकास को एक नई दिशा प्रदान की है। डिजिटल अर्थव्यवस्था के प्रभाव को विभिन्न पहलुओं में देखा जा सकता है, जैसे कि सकल घरेलू उत्पाद पर योगदान, रोजगार सृजन, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों पर प्रभाव, और ग्रामीण व शहरी अर्थव्यवस्था में डिजिटल क्रांति।

भारत की अर्थव्यवस्था में डिजिटल क्षेत्र का योगदान निरंतर बढ़ता जा रहा है। हाल के वर्षों में, डिजिटल तकनीक और ऑनलाइन व्यापार के विस्तार से जीडीपी में डिजिटल अर्थव्यवस्था की भागीदारी तेज़ी से बढ़ी है। डिजिटल अर्थव्यवस्था के कारण वित्तीय सेवाओं, ई–कॉमर्स, डिजिटल भुगतान प्रणाली, स्टार्टअप सेक्टर और आईटी उद्योग में तेज़ी आई है। रिपोर्टों के अनुसार, भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था का जीडीपी में योगदान वर्ष 2022 में लगभग 11 प्रतिशत था, जो 2030 तक 20 प्रतिशत तक पहुँचने की संभावना है।

डिजिटल अर्थव्यवस्था का भारतीय जीडीपी में योगदान लगातार बढ़ रहा है। डिजिटल बैंकिंग, ई–कॉमर्स, और वित्तीय सेवाओं की बढ़ती लोकप्रियता ने आर्थिक गतिविधियों का विस्तार किया है। ऑनलाइन भुगतान प्रणालियों के तेजी से अपनाए जाने से अर्थव्यवस्था के आकार में वृद्धि हुई है। ई–कॉमर्स और डिजिटल व्यापार के माध्यम से व्यापारिक अवसरों में वृद्धि हुई है, जिससे व्यवसायों को एक व्यापक बाजार तक पहुँचने का अवसर मिला है। स्टार्टअप इकोसिस्टम को डिजिटल नवाचार से बल मिला है, जिससे विभिन्न उद्योगों में नए व्यापारिक अवसर उभर रहे हैं। भारत सरकार ने डिजिटल अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए 'डिजिटल इंडिया मिशन' और 'मेक इन इंडिया' जैसी पहलें शुरू की हैं, जो नवाचार और स्टार्टअप को आर्थिक विकास से जोड़ने में

सहायक रही हैं।[3]

डिजिटल अर्थव्यवस्था के विकास ने पारंपरिक रोजगार क्षेत्रों के साथ–साथ नए डिजिटल नौकरियों को भी जन्म दिया है। आईटी और सॉफ्टवेयर सेवाओं में वृद्धि से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, डेटा साइंस, और क्लाउड कंप्यूटिंग जैसी नौकरियों की माँग बढ़ी है। ई–कॉमर्स और डिजिटल मार्केटिंग के विस्तार से ऑनलाइन व्यापार, सोशल मीडिया प्रबंधन और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर पैदा हुए हैं। 'वर्क फ्रॉम होम' मॉडल और गिग इकोनॉमी के विस्तार से डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से फ्रीलांसिंग को बढ़ावा मिला है। सरकार द्वारा डिजिटल साक्षरता कार्यक्रमों की शुरुआत से लोगों को डिजिटल कौशल प्राप्त करने और रोजगार के नए अवसर तलाशने का अवसर मिला है। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, डिजिटल अर्थव्यवस्था से जुड़े नौकरियों में 2025 तक 30 प्रतिशत की वृद्धि होने की संभावना है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि डिजिटल क्रांति ने रोजगार सृजन को नई ऊँचाइयों तक पहुँचाया है।

MSME सेक्टर भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है, और डिजिटल तकनीक के बढ़ते उपयोग से इसे कई लाभ प्राप्त हुए हैं। ऑनलाइन व्यापार और डिजिटल मार्केटिंग के विस्तार से डैडम् इकाइयाँ अब अपने उत्पादों को ई–कॉमर्स प्लेटफार्मों पर बेच सकती हैं। डिजिटल भुगतान प्रणाली के उपयोग से डैडम् व्यवसायों को तेज़ और सुरक्षित भुगतान प्रणाली का लाभ मिला है। क्लाउड कंप्यूटिंग और ऑटोमेशन जैसी डिजिटल तकनीकों के प्रयोग से छोटे और मध्यम व्यवसाय अधिक दक्ष और प्रतिस्पर्धी बन रहे हैं। केंद्र सरकार की 'मुद्रा योजना' और 'डिजिटल डैडम् योजना' जैसी पहलें डैडम् सेक्टर को डिजिटलीकरण की दिशा में आगे बढ़ने में मदद कर रही हैं। डिजिटल तकनीक ने डैडम् क्षेत्र को अधिक प्रतिस्पर्धी और कुशल बनाया है, जिससे व्यापार के नए अवसर खुले हैं और वैश्विक बाजारों तक उनकी पहुँच बढ़ी है।[4]

डिजिटल क्रांति ने भारत के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को नया स्वरूप दिया है। डिजिटल बैंकिंग और वित्तीय समावेशन के माध्यम से सरकार की 'जन धन योजना' जैसी सेवाओं ने ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित किया है। कृषि में डिजिटल नवाचारों के कारण किसान मोबाइल ऐप के माध्यम से कृषि उत्पादों की बिक्री कर सकते हैं, जिससे कृषि क्षेत्र में पारदर्शिता और प्रतिस्पर्धा बढ़ी है। ई–कॉमर्स कंपनियाँ अब ग्रामीण क्षेत्रों से उत्पादों की बिक्री को प्रोत्साहित कर रही हैं, जिससे स्थानीय उत्पादकों को एक व्यापक बाजार उपलब्ध हुआ है। डिजिटल शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में ऑनलाइन शिक्षा और टेलीमेडिसिन सेवाएँ तेजी से लोकप्रिय हो रही हैं, जिससे लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएँ और शिक्षा तक आसान पहुँच मिल रही है। शहरी अर्थव्यवस्था में डिजिटल सेवाओं के विस्तार के कारण स्टार्टअप और डिजिटल बिजनेस को बढ़ावा मिला है। भारत के महानगरों में डिजिटल स्टार्टअप का तेजी से विकास हुआ है, जिससे नए उद्यमों को सशक्त बनाने में सहायता मिली है। सरकार की स्मार्ट सिटी योजना में डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा दिया गया है, जिससे शहरी बुनियादी ढाँचा अधिक स्मार्ट और कुशल बन रहा है।5 डिजिटल भुगतान प्रणाली के बढ़ते उपयोग से शहरी क्षेत्रों में कैशलेस ट्रांजेक्शन अधिक लोकप्रिय हो गए हैं, जिससे डिजिटल अर्थव्यवस्था का प्रभाव और अधिक व्यापक हो गया है।

डिजिटल वित्तीय प्रणाली और बैंकिंग क्षेत्र में परिवर्तन

भारत में डिजिटल वित्तीय प्रणाली और बैंकिंग क्षेत्र में पिछले कुछ दशकों में अभूतपूर्व परिवर्तन हुए हैं। तकनीकी नवाचारों, इंटरनेट की बढ़ती पहुँच और सरकार की डिजिटल इंडिया पहल के कारण बैंकिंग प्रणाली को डिजिटल रूप से सशक्त किया गया है। पारंपरिक बैंकिंग प्रणाली जहाँ शाखाओं और भौतिक लेन–देन तक सीमित थी, वहीं डिजिटल बैंकिंग ने वित्तीय सेवाओं को अधिक सुगम, त्वरित और सुरक्षित बना दिया है। डिजिटल बैंकिंग ने भारतीय बैंकिंग प्रणाली में क्रांतिकारी परिवर्तन किया है। पहले जहाँ बैंकों में लंबी कतारें, धीमी सेवाएँ और कागजी दस्तावेज़ीकरण जैसी समस्याएँ थीं, वहीं अब डिजिटल बैंकिंग ने इन समस्याओं को काफी हद तक दूर कर दिया है। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के माध्यम से बैंकिंग सेवाएँ अब 24X7 उपलब्ध हो गई हैं।

डिजिटल बैंकिंग और ऑनलाइन ट्रांजेक्शन प्रणाली ने भारत में वित्तीय सेवाओं के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाया है। नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, यूपीआई और आईएमपीएस जैसी सेवाओं के माध्यम से अब लोग किसी भी समय और कहीं से भी धन हस्तांतरण कर सकते हैं। इस परिवर्तन से लेन–देन की गति में वृद्धि हुई है और साथ ही सुरक्षा के नए मानक स्थापित हुए हैं। डिजिटल बैंकिंग के विस्तार से अब कागजी दस्तावेज़ों की

आवश्यकता कम हो गई है, क्योंकि डिजिटल हस्ताक्षर, ई–केवाईसी और आधार लिंकिंग जैसी सुविधाओं ने पेपरलेस बैंकिंग को बढ़ावा दिया है। हालाँकि, इसके साथ साइबर सुरक्षा और डेटा गोपनीयता की चुनौतियाँ भी सामने आई हैं। फिशिंग, डेटा चोरी और ऑनलाइन धोखाधड़ी जैसी घटनाएँ बढ़ी हैं, जिससे उपभोक्ताओं की सुरक्षा को लेकर चिंता बनी हुई है। इन खतरों को रोकने के लिए बैंकों को मजबूत साइबर सुरक्षा उपाय अपनाने की आवश्यकता है। इसके अलावा, डिजिटल हेल्पडेस्क और एआई आधारित ग्राहक सेवा के कारण अब बैंकिंग सेवाएँ अधिक प्रभावी और सुविधाजनक हो गई हैं। इन सभी परिवर्तनों का असर केवल शहरी क्षेत्रों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी डिजिटल बैंकिंग सेवाओं की पहुँच बढ़ी है, जिससे वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिला है।[6]

क्रिप्टोकरेंसी और ब्लॉकचेन तकनीक ने वैश्विक वित्तीय प्रणाली में एक नई क्रांति की शुरुआत की है। भारत में क्रिप्टोकरेंसी को अब तक कानूनी मान्यता नहीं मिली है, लेकिन इसके उपयोग और प्रभाव को लेकर लगातार चर्चा हो रही है। विकेंद्रीकृत वित्तीय प्रणाली (डीएफआई) के रूप में क्रिप्टोकरेंसी ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों पर निर्भरता को कम करने का विकल्प प्रस्तुत किया है। यदि क्रिप्टोकरेंसी को व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है, तो यह पारंपरिक बैंकिंग प्रणाली को चुनौती दे सकता है। हालाँकि, इसकी अस्थिरता और नियामक अनिश्चितता के कारण भारत में इसे पूर्ण रूप से लागू करने में संदेह बना हुआ है। इसके विपरीत, भारतीय रिजर्व बैंक ने डिजिटल मुद्रा (सीबीडीसी) के रूप में डिजिटल रुपये की अवधारणा पर कार्य किया है, जो ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित होगी और जिसे आधिकारिक रूप से भारत में क्रिप्टोकरेंसी का एक कानूनी विकल्प माना जा सकता है। ब्लॉकचेन तकनीक ने वित्तीय सेवाओं में पारदर्शिता, सुरक्षा और धोखाधड़ी की रोकथाम को मजबूत किया है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का उपयोग अब डिजिटल व्यापार और वित्तीय लेन–देन को अधिक प्रभावी बना रहा है। कई भारतीय बैंक अब डिजिटल लेन–देन, डेटा सुरक्षा और क्रेडिट स्कोरिंग जैसी सेवाओं में ब्लॉकचेन तकनीक को अपनाने पर विचार कर रहे हैं, जिससे वित्तीय प्रणाली को अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाया जा सके।

डिजिटल भुगतान प्रणाली ने भारत में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पहले जहाँ गरीब और ग्रामीण जनता के लिए बैंकिंग सेवाएँ सुलभ नहीं थीं, वहीं डिजिटल तकनीक के प्रसार ने इसे संभव बना दिया है। यूपीआई और मोबाइल वॉलेट्स जैसे प्लेटफार्मों ने लेन–देन को सरल बना दिया है और नकदी रहित अर्थव्यवस्था की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत खोले गए बैंक खातों के माध्यम से डिजिटल बैंकिंग को गरीबों तक पहुँचाने में मदद मिली है। लाखों लोगों ने जीरो–बैलेंस बैंक खातों के माध्यम से डिजिटल बैंकिंग का लाभ उठाया है। इसके अलावा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में डिजिटल भुगतान का उपयोग बढ़ाने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी), डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) और ई–नाम जैसी योजनाएँ शुरू की गई हैं।[7]

डिजिटल अर्थव्यवस्था और उपभोक्ता व्यवहार

भारत में डिजिटल अर्थव्यवस्था का विस्तार उपभोक्ता व्यवहार में एक महत्वपूर्ण बदलाव का कारण बना है। प्रौद्योगिकी के निरंतर विकास, इंटरनेट की बढ़ती पहुँच, और सरकार की डिजिटल इंडिया पहल ने उपभोक्ताओं के जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित किया है। डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से अब उपभोक्ता अधिक सुविधाजनक और कुशल तरीके से खरीदारी, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं। डिजिटल अर्थव्यवस्था के विकास के साथ, भारत में उपभोक्ताओं की खरीदारी की आदतें पारंपरिक खुदरा दुकानों से डिजिटल प्लेटफार्मों की ओर स्थानांतरित हो गई हैं। ई–कॉमर्स और ऑनलाइन भुगतान प्रणालियों के विकास के कारण उपभोक्ताओं को अधिक विकल्प, बेहतर मूल्य निर्धारण और सुविधाजनक शॉपिंग अनुभव प्राप्त हो रहा है। डिजिटल भुगतान प्रणालियों के उपयोग में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। यूपीआई, डिजिटल वॉलेट्स जैसे गूगल पे, फोनपे, पेटीएम के साथ–साथ नेट बैंकिंग के माध्यम से कैशलेस ट्रांजेक्शन की संख्या बढ़ी है।8 भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार, 2022 में भारत में डिजिटल भुगतान का लेन–देन मूल्य 1 ट्रिलियन डॉलर के पार पहुँच गया। इसके अतिरिक्त, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब उपभोक्ता व्यवहार को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, जहाँ इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग और ब्रांड प्रमोशन के माध्यम से उपभोक्ताओं का झुकाव नए उत्पादों की ओर हो रहा है।

डिजिटल अर्थव्यवस्था ने शिक्षा प्रणाली में भी एक महत्वपूर्ण परिवर्तन लाया है। ऑनलाइन शिक्षा और डिजिटल कौशल विकास ने न केवल शिक्षा की पहुँच को विस्तारित किया, बल्कि भारत में नए करियर विकल्पों को भी बढ़ावा दिया है। कोविड–19 महामारी के दौरान स्कूलों और कॉलेजों के बंद होने से ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली को अप्रत्याशित गति मिली। बायजूस, अनअकैडमी, वेदांतु, कॉर्सेरा, यूडेमी जैसे ऑनलाइन प्लेटफार्मों ने छात्रों को डिजिटल माध्यम से शिक्षा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। डिजिटल कौशल विकास के क्षेत्र में भी नए अवसर उभरे हैं। सरकार और निजी संस्थान अब डिजिटल कौशल विकास कार्यक्रमों को बढ़ावा दे रहे हैं, जिससे डिजिटल अर्थव्यवस्था में रोजगार की संभावनाएँ बढ़ी हैं। डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, कोडिंग, डिजिटल मार्केटिंग और साइबर सुरक्षा जैसी डिजिटल स्किल्स की माँग लगातार बढ़ रही है। ऑनलाइन शिक्षा ने ग्रामीण और वंचित समुदायों को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्राप्त करने में सहायता की है, हालाँकि इंटरनेट कनेक्टिविटी, डिजिटल डिवाइड और सस्ते स्मार्ट डिवाइसेस की उपलब्धता अभी भी कुछ प्रमुख चुनौतियाँ बनी हुई हैं। डिजिटल तकनीक अब स्वास्थ्य सेवाओं तक भी पहुँच चुकी है, जिससे लोगों को दूरस्थ स्थानों पर भी उन्नत चिकित्सा सेवाएँ प्राप्त हो रही हैं। टेलीमेडिसिन, ऑनलाइन कंसल्टेशन और डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड जैसे नवाचारों ने हेल्थकेयर सिस्टम को अधिक प्रभावी बना दिया है।9 डिजिटल हेल्थकेयर के क्षेत्र में टेलीमेडिसिन सेवाएँ अब दूर–दराज के क्षेत्रों में भी स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान कर रही हैं।

सरकार ने राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत की है, जिसमें नागरिकों के स्वास्थ्य रिकॉर्ड को डिजिटल रूप में संग्रहीत किया जाएगा। इससे मरीजों को किसी भी अस्पताल में सुविधाजनक उपचार प्राप्त करने में सहायता मिलेगी और मेडिकल हिस्ट्री को सुरक्षित रूप से संग्रहित किया जा सकेगा। ई–फार्मेसी के बढ़ते चलन के कारण अब उपभोक्ता फार्मईज़ी, मेडलाइफ, नेटमेड्स जैसी सेवाओं के माध्यम से दवाइयाँ ऑनलाइन मँगवा सकते हैं। यह सुविधा विशेष रूप से बुजुर्गों और दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए उपयोगी साबित हो रही है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग स्वास्थ्य सेवाओं में भी बढ़ रहा है, जिससे रोगों के निदान और उपचार की प्रक्रिया में उन्नति हो रही है। ।प् आधारित हेल्थ चौटबॉट्स और स्मार्ट डायग्नोस्टिक टूल्स स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक कुशल और प्रभावी बना रहे हैं।10 डिजिटल हेल्थकेयर सेवाओं के विस्तार से भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है, जिससे उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएँ अधिक लोगों तक पहुँच रही हैं।

निष्कर्ष

भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था हाल के वर्षों में तेजी से विकसित हुई है, जिससे देश के आर्थिक और सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिले हैं। डिजिटल बैंकिंग, ई–कॉमर्स, ऑनलाइन शिक्षा, और स्वास्थ्य सेवाओं ने डिजिटल क्रांति को एक नई दिशा दी है। सरकार की डिजिटल इंडिया पहल और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने वाली नीतियों ने भारत को डिजिटल परिवर्तन की ओर अग्रसर किया है। हालाँकि, डिजिटल अर्थव्यवस्था के व्यापक और दीर्घकालिक प्रभाव को सुनिश्चित करने के लिए कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान देने की आवश्यकता है। डिजिटल अर्थव्यवस्था भारत के आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण घटक बन चुकी है। सरकार द्वारा डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, और डिजिटल भुगतान प्रणाली को बढ़ावा देने से भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से डिजिटल रूप से विकसित हो रही है। हालाँकि, डिजिटल अवसंरचना, साइबर सुरक्षा, और डिजिटल समावेशन जैसी चुनौतियों को दूर करना अभी भी आवश्यक है। यदि सरकार, निजी क्षेत्र और नागरिक समाज मिलकर डिजिटल सेवाओं को सुलभ, सुरक्षित और प्रभावी बनाते हैं, तो आने वाले वर्षों में भारत दुनिया की अग्रणी डिजिटल अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन सकता है। डिजिटल नवाचार और नीति सुधारों के माध्यम से भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था और अधिक समावेशी, पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी बन सकती है।

संदर्भ सूची

1. गुप्ता, एस. (2019). डिजिटल अर्थव्यवस्था और भारत का विकास. नेशनल बुक ट्रस्ट, नई दिल्ली, पृ. 12।
2. मिश्रा, एस. (2022). स्टार्टअप इंडिया और डिजिटल इकोसिस्टम. पेंगुइन बुक्स, चेन्नई., पृ. 45।
3. शर्मा, आर. (2021). डिजिटल इंडिया– एक नई क्रांति. प्रभात प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ. 94।
4. वही, पृ. 95।
5. शर्मा, पी. (2021). डिजिटल शिक्षा के माध्यम से कौशल विकास. इंडियन एजुकेशनल रिव्यू, 8(1), **पृ.**

30–31।
6. मेनन, आर. (2018). डिजिटल करेंसीः चुनौतियाँ और अवसर. जर्नल ऑफ़ डेवलपमेंट स्टडीज़, 12(4), 79.
7. सिंह, डी. (2022). डिजिटल समावेशन– ग्रामीण भारत की दिशा में. ओरिएंट ब्लैकस्वान, हैदराबाद, पृ. 85।
8. वही, पृ. 88।
9. नायर, एस. (2021). डिजिटल सुरक्षा और डेटा प्राइवेसी. जेको पब्लिशिंग हाउस, चेन्नई, पृ. 140।
10. अग्रवाल, पी. (2018). कृत्रिम बुद्धिमत्ता और अर्थव्यवस्था. विवेकानंद प्रकाशन, लखनऊ, पृ. 157।

Cite this Article-

'डॉ0 संजीव रतन गुप्ता', 'आधुनिक भारत में डिजिटल अर्थव्यवस्था का विकास और उसका प्रभाव', Research Vidyapith International Multidisciplinary Journal (RVIMJ), ISSN: 3048-7331 (Online), Volume:2, Issue:03, March 2025.

Journal URL- https://www.researchvidyapith.com/
DOI- 10.70650/rvimj.2025v2i3001
Published Date- 02 March 2025